देश में कागज की वार्षिक मांग और उत्पादन

959. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज की राज्य वार वार्षिक मांग कितनी है और इसका वार्षिक उत्पादन कितना है,

(ख) कागज का प्रति वर्ष कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है,

(ग) क्या देश में कागज के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में लघु कागज मिलों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस देने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में कागज की आवश्यकता के राज्यवार आँकड़े उपलब्ध नहीं है । कागज और गत्ते की वर्तमान वार्षिक मांग और उत्पादन क्रमशः लगभग 21.5 लाख मी. टन और 21.28 लाख मी० टन है।

(ख) 1992-93 के दौरान 39,159 मी. टन कागज और कागज उत्पादों का आयात किया गया था।

(ग) लकड़ी पर आधारित कच्चे माल की कमी है किन्तु खोई और कृषि अवशेषों जैसे अपरम्परागत कच्चे माल की बहुतायत है ।

(घ) नयी औद्योगिक नीति के अधीन ब.ई, पटसन, कृषि अवशेषों और रद्दी कागज से निकलने वाली लुगदी का कम से कम 75% प्रयोग करने वाली कागज मिलों की स्थापना स्थल संबंधी शर्तें के अधीन अनिवार्य लाइसेंसीकरण से छूट दी गई है । उन्हें औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है । अगस्त, 1991 और अक्तूबर, 1993 के बीच 190 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा, आशय पत्रों के लिए प्राप्त 24 आवेदनों में से 7 का अनुमोदन कर दिया गया है।

Impact of liberalisation on SSI units

960. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have examined the impact of liberalisation on the survival of small scale Industries ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken to check the formation of cartels in these sectors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (c) Government has constantly been reviewing the impact of liberalisation and is of the view that this will help this sector to grow at faster rate: Government, however is also aware of the apprehensions expressed from various quarters on the adverse impact of liberalisation including formation of cartels, etc. With this end in view, the policy of reservation is being continued, fiscal concessions have been enhanced and to make SSI units more competitive, Government is providing support for modernisation, assistance for quality upgradation, etc. A Committee under the Chairmanship of Shri P. R. Nayak, former Dy. Governor of RBI was constituted to examine the adequacy of institutional credit and related aspects. The Committee has submitted its report in September, 1992. RBI has already announced its acceptance of most of the recommendations. So far as formation of cartels is concerned these are regulated by MRTP Act.